गरीब आदमी की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता : मनोहर लाल

करनाल। मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से अंत्योदय मेलों की ली फीडबैक, कहा- मेलों में जो खामिया नजर आई तुरंत करें दुरूस्त, अगले 15 दिनों में दोबारा लगने वाले मेलों में वितरित करें स्वीकृत पत्र, काउंसलर टीम घर-घर जाकर पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए करें प्रेरित।

करनाल 01 दिसम्बर , मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब व्यक्तियों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से खंड स्तर पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित किए गए मेलों की चंडीगढ़ से वीसी के माध्यम से फीडबैक ली तथा सुधार के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने जिलों से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मेलों में जो खामिया नजर आई, उन्हें दुरूस्त करें तथा 18 से 60 वर्ष तक की आयु के हर गरीब आदमी को किसी ना किसी विभाग की स्कीम से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अंत्योदय मेलों से एक दिन पहले हर जिला में काउंसलर की टीम घर-घर जाकर पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर ना केवल स्वयं आत्मनिर्भर बने बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दिलाने में सहायक सिद्ध हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि वार्षिक 1 लाख रूपये से कम आय वाले गरीब लोगों की सूची में शामिल अंतिम व्यक्ति की आमदनी बढ़ाना है और जिला में हर परिवार की आमदनी 1 लाख रूपये वार्षिक से उपर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी को लेकर सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत खंड स्तर पर मेलों का आयोजित करवाए जा रहे है। सभी विभागों के अधिकारी इन मेलों के सफल आयोजन को लेकर मिलजुल कर कार्य करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत तीन चरणों में खंड स्तर पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जाना है। जिसके प्रथम चरण में वार्षिक एक लाख रूपये से कम आय वाले परिवार , दूसरे चरण में 1 लाख 80 हजार रूपये से कम तथा तीसरे चरण में 3 लाख रूपये से कम आय वाले लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

वीसी में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मुख्यमंत्री को खंड स्तर पर आयोजित कुंजपुरा मेले का अनुभव सांझा करते हुए सुझाव दिया कि मेले में आए सक्षम युवाओं को रोजगार विभाग की वरिष्ठता सूची में ना रखकर प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए फीस माफ की जाए तथा पीपीपी कार्ड होने के बावजूद जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र व रिहायशी प्रमाण पत्र को अनिवार्य ना किया जाए। इस सुझाव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत संज्ञान लिया और फीस माफ करने की घोषणा की और यह भी कहा कि लोगों के परिवार पहचान पत्र में जाति, आय तथा रिहायशी का प्रमाण सत्यापित होने के कारण इनकी जमा करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा सक्षम युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया करवाने का निर्णय लिया।

कृषि कानूनों की वापसी के समय संसद में हंगामा क्यों

करनाल। 29 नवंबर को लोकसभा में जब सरकार की ओर से तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया हो रही थी, तब कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इससे कानून वापसी के समय लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार कहा कि वे कानून वापसी के प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी दलों के सांसद जोर जोर से चिल्लाते रहे। सवाल उठता है कि कृषि कानूनों की वापसी के समय विपक्षी सांसदों ने हंगामा क्यों किया? विपक्षी दलों की इस राजनीति को किसानों को समझना चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने स्वार्थ पूरे कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष से मांग की जा रही थी कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लें, लेकिन जब कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। देश को यह जानने का अधिकार है कि सरकार ने किन कारणों से कानूनों को वापस लिया। लेकिन विपक्षी दल के सांसद देशवासियों को अपने अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। पिछले दिनों जब गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी, तब दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के नेताओं ने कहा कि संसद में कानून वापसी के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। ऐसे नेताओं का कहना रहा कि हमें प्रधानमंत्री की घोषणा पर भरोसा नहीं है। किसानों के नेताओं ने कुछ भी कहा हो, लेकिन सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव रख दिया। सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा में कानून वापसी का प्रस्ताव मंजूर भी हो गया। यानी प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी उस पर सरकार ने अमल कर दिया है। दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान अभी भी जाम लगा कर बैठे हैं, वे माने या नहीं लेकिन कुछ लोग किसानों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। सब जानते हैं कि एक वर्ष पहले जब कृषि कानूनों को संसद में मंजूर किया गया, तब भी सांसदों ने हंगामा किया था। इसलिए मंजूरी के समय भी चर्चा नहीं हो सकी और अब जब कानून को वापस लिया जा रहा है, तब भी विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी है। असल में विपक्षी दलों का मकसद किसानों की मदद करना नहीं है। विपक्षी दलों का मकसद किसानों की आड़ में अपनी राजनीति करना है। सवाल यह भी है कि जब संसद से कृषि कानून रद्द हो गए हैं, तब दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन क्यों किया जा रहा है। देश का आम किसान और नागरिक अब आंदोलन को चलाने वालों के बारे में अच्छी तरह समझ गया है।

6.48 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई

करनाल। दि करनाल सहकारी चीनी मिल लिमिटेड की प्रबंध निदेशक अदिति ने बताया कि मिल द्वारा अब तक 6.48 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की जा चुकी है। मिल ने अपना पिराई सत्र 9 नवम्बर 2021 से शुरू कर दिया है तथा मिल द्वारा पूरी क्षमता के साथ पिराई का कार्य जारी है।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि मिल द्वारा किसानों के गन्ने की ट्रालियों को समय पर खाली किया जाता है तथा मिल अपनी पूरी पिराई क्षमता 35 हजार क्विंटल प्रतिदिन की दर से कर रहा है। इस मिल द्वारा 56 लाख क्विंटल गन्ना पिराई का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि अपनी पर्ची किसी दूसरे मिल या अन्य प्रांतों के किसानों को न दें। यदि कोई किसान ऐसा करता पाया जाता है तो उनका बाँड व पर्ची बंद कर दी जाएगी व उनका बाँड कैंसल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिल के गन्ना अधिकारियों द्वारा रोजाना दूसरे प्रांतों व मिल के एरिया से बाहर से गन्ने की ट्रालियां पकड़ी जा रही हैं और उन किसानों के बाँड व पेमेंट बंद की जा रही है। इसलिए सभी किसान अपनी पर्ची मिल एरिया के बाहर व दूसरे प्रांतों के किसानों को न दें तथा पिराई कार्य में मिल प्रशासन का सहयोग करें।

एमडी महोदया यह बात छुपा रही है कि मिल के नवीनीकरण के बाद जो पिराई 35000 क्विंटल प्रतिदिन होनी चाहिये थी वह केवल 20-22 हजार क्विंटल हो पा रही है। इससे जो चीनी बन भी रही है उसका अधिकांश बर्बाद हो रहा है। बीते सप्ताह एक वीडियों में उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि जब तक मिल द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिजली को बाहर भेजने का इंतजाम नही हो पायेगा तब तक मिल पूरी क्षमता पर नहीं चल सकती, उन्ही के अनुसार यह काम जनवरी से पहले होने वाला नहीं है।

मुख्यमंत्री के सात साल में कंगाल बना हरियाणा: त्रिलोचन

सात साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे सात सवाल

करनाल। करनाल के विधायक तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री के सात साल पूरे होने पर आज कांग्रेस ने विरोध और सबाल दिवस मनाया। आज कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह की अगुआई में सेकडो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विरोध मार्च निकाल कर सीटीएम को ज्ञापन दिया।बाद में मंहगाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका।इस अवसर पर नारेवाजी की गई।इस अवसर पर कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने बताया कि हरियाणा में बीजेपी के सात साल लोगो के लिये जी का जंजाल साबित हुया। जो कुछ कांग्रेस ने छोड़ा उसे बीजेपी ने बर्वाद कर दिया

आज प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। मंहगाई ने लोगो को कंगाल कर दिया है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आप की सरकार तथा करनाल की विधायकी के सात साल पूरे हो रहे है।हरियाणा के साथ करनाल के लोगो को आपसे काफी आशाएं थी। आप हरियाणा में लोकराज लेकर आएंगे।आप जिस तरह से अपनी सरकार के सात बड़े काम गिनवा रहे हो।

करनाल के लोगो की तरफ से हम आपसे सात सबाल कर रहे है।करनाल आपसे उत्तर चाहता है।आप सबसे ज्यादा जनविरोधी विधायक सावित हुए हो।

यह है मुख्यमंत्री से सात सवाल

- क्या मुख्यमंत्री नगरी अपराधियो से सुरक्षित है। भष्टाचार मुक्त है?
- क्या स्मार्ट सिटी में गड़बड़ घोटाला नही है।शहर में वाई फाई ,ई रिक्शा,शो-रोम,सिटी बस सर्विस,बाई पास, मुगल केनाल पार्ट 3,नगरनिगम दफ्तर की जगह मल्टी पार्किंग स्लम बस्तियों में पानी, लाइट, सड़को,तथा 80 करोड़ खर्च कर सीवरेज व्यबस्था सब ठीक चल रहा है? श्वेत पत्र जारी कर कर स्थिति साफ करे?
- क्या किसा मजदूर-व्यापारी-कर्मचारी -वेरोजगारो का शोषण नही हो रहा है? एग्रो माल की नीलामी उचित है ?
- क्या मुख्यमंत्री जी आप करनाल के लोगो के लिये बढ़ा प्रोजेक्ट ले कर आये। यहां के बेरोजगारों को व्यापारियों को क्या फायदा हुआ।करोडो रुपया फूंक कर रोजगार की दिशा में कोई बड़ा काम हुया?
- क्या पेट्रोल डीजल तथा बढ़ती मंहगाई से जनता त्रस्त नही है?
- क्या साधनोंऔर डॉक्टरों के अभाव में कल्पना चावला मेडिकल कालेज रेफर सेंटर नही बन गया है?
- क्या सीएम साहव कोरोना काल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे करनाल निवासियों के सुख और दुख में शामिल हुये।

यह थे उपस्थित

इस अवसर पर ए आईसीसी की सदस्य श्रीमती कमल मान, धर्मपाल कौशिक,सतपाल जानी,रानी काम्बोज,सुरेंद्र कालखा,एडवोकेट नृपेंद्र मान, होशियार सिंह,प्रेम मलवानिया,परमजीत भारद्वाज,,गगन मेहता,जितेंद्र शर्मा,बलवान पठान,चरणदेव कामरा,सुनहरा वाल्मीकि रविदास पहलवान,विनोद काला,परम जीत वालमीकि,नरेंद्र अग्घी,ठाकुरदास एक्स एमसी,जतिंदर पांचाल,पुनीत अरोरा,प्रकाश बीर, बलजीत चौहान आदि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में कीर्तिमान बनाया तो मिलेगी आर्थिक सहायता : डॉ. चौहान

करनाल। राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली विभिन्न खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने या कीर्तिमान बनाने वाले गरीब परिवारों के खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिन खिलाड़ियों के माता-पिता हरियाणा के किसी भी सरकारी या वाणिज्यिक संस्थान में बतौर श्रमिक पंजीकृत हैं, उन खिलाड़ियों को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड आर्थिक सहायता प्रदान करता है ताकि प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। इस प्रावधान के बारे में श्रम कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह जानकारी हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने मुनक के परमवीर सैनिक स्पोर्ट्स एकैडमी में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान दी।

डॉ. चौहान ने कहा कि देश के हर राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से कोई न कोई व्यवस्था जरूर होती है। लेकिन हम सब को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं सम्मान के लिए जितनी सुविधाएं हरियाणा सरकार की खेल नीति में हैं, इतनी व्यवस्था किसी भी अन्य राज्य की खेल नीति में नहीं है। ओलंपिक और एशियाड जैसी अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में हरियाणा के युवाओं द्वारा पदक जीतकर लाना इसी का सुपरिणाम है। ऐसी प्रतियोगिताओं में देश को मिले कुल पदकों में आधे से अधिक का योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का ही होता है।

डॉ. चौहान ने कहा कि परमवीर सैनिक स्पोर्ट्स एकेडमी के भी 100 से ज्यादा खिलाड़ी अब विभिन्न क्षेत्रों में अग्रिम मोर्चों पर पहुंच चुके हैं। अपने खेल के दम पर वह सरकारी नौकरियों में अपना झंडा गाड़ चुके हैं। प्राचीन गुरुकुल में जितना सम्मान गुरुओं का होता था, वह परंपरा हमारी स्पोर्ट्स एकेडमियों में आज भी कायम है। खेल में आगे बढ़ने के लिए कोच का मार्गदर्शन जरूरी होता है। इसीलिए उनका सम्मान होना चाहिए।

डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि एक कामयाब खिलाड़ी होने के लिए जरूरी है कि वह हर परिस्थिति में निरंतर खिलखिलाते रहें। इवेंट में हिस्सा लेने के बाद घर जाते समय हर खिलाड़ी यह संकल्प लेकर जाए कि सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहूंगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिभागियों को अपने साथी खिलाड़ियों को श्रम कल्याण बोर्ड की आर्थिक सहायता योजना से अवगत कराना चाहिए ताकि किसी जरूरतमंद परिवार का भला हो सके।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, जिला महामंत्री राजबीर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण लाठर, जिला कार्यकारिणी सदस्य राजेश आर्य, मंडल अध्यक्ष संदीप सैनी गोल्ली, मंडल महामंत्री अमित राणा व विनोद शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष नितिन राणा, मंडल सचिव नाथीराम व सुरेंद्र कश्यप, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष जयभगवान जांगड़ा, विवेक राणा, दीपेंद्र, ओमप्रकाश, शिव मंदिर कमेटी के सितेंद्र, प्रदीप शर्मा, मंदीप पनौड़ी, दर्शन शर्मा, अमर सिंह और सलमदीन भी मौजूद रहे।